VISION IAS

19 DEC 2020

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1415)

Name of Candidate	SANDEEP KUMAR		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	473817
Center	MN	Date	16/12/2020

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

Signature of Examiner

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. There have been arguments that direct benefit cash transfers should replace the supply of food through the public distribution system. Do you agree with such arguments? Give reasons in support of your answer.

(150 words) 10

यह तर्क दिया जाता रहा है कि प्रत्यक्ष लाभ नकद हस्तांतरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति का स्थान ले लेना चाहिए। क्या आप ऐसे तर्कों से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही उत्तरदायी है यह 67% जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।

प्रत्यक्ष लाभ नकद हस्तांतरण में राशन के स्थान पर लोगों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से धन हस्तान्तरण करना है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के पक्ष में तर्क :-

1. भ्रष्टाचार एवं रिसाव की समस्या का समाधान।
2. सरकार की खाद्य सब्सिडी पर बिल का कम होना।
3. लोगों द्वारा अपनी इच्छानुसार एवं पोषक तत्वों से युक्त खाद्यान्न खरीदना।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के विपक्ष में तर्क :-

1. लोग प्राप्त धन को खाद्यान्न के स्थान पर अन्य वस्तुओं पर खर्च करना
2. सरकार किसानों से MSP पर अधिग्रहण नहीं कर पाएगी।
3. खाद्यान्न की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।
4. ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग अवसंरचना का अनुपस्थित होना।
5. खाद्यान्न मूल्यों में उतार-चढ़ाव से भी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। जैसे- दाल, चावल व गेहूँ के मूल्य परिवर्तित होने पर।

समग्रतः हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को पायलट आधार पर चला सकते हैं। इस गुण-दोष के व्यापक विश्लेषण के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तानांतरण की ओर बढ़ना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. What do you understand by the term 'participatory budgeting'? Identify the challenges associated with participatory budgeting in India.

(150 words) 10

आप 'सहभागितापूर्ण बजटन' शब्दावली से क्या समझते हैं? भारत में सहभागितापूर्ण बजटन से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कीजिए।

सहभागितापूर्ण बजट से तात्पर्य लोगों की भागीदारी से बजट के तैयार करने से है इससे लोगों की आवश्यकता के आधार पर संसाधन के आवंटन में मदद मिलेगी।

सहभागितापूर्ण बजट के पक्ष में तर्क :-

1. लोगों की संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका।
2. डाउन टू टॉप अप्रोच को बढ़ावा।
3. महिला, बच्चों एवं सुभेद्य वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।

इससे संबंधित चुनौतियाँ :-

1. राष्ट्रीय एवं व्यापक महत्व के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. लोगों के पास बजट में भागीदारी हेतु पर्याप्त ज्ञान एवं आंकड़ों का अभाव।

3. प्राथमिकता तय करने में लोगों का विवेक जनभावनाओं से ग्रसित हो सकता है।

4. यह एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और सभी लोगों के विचारों का समावेश नहीं कर पाएगी।

सहभागितापूर्ण बजट एक प्रगतिशील विचार है जो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय करेगा। इसको सीमित एवं लोगों की आवश्यकताओं को जानने हेतु सरकार उपयोग कर सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Inclusive growth in an economy itself negates the need for a Universal Basic Income. Discuss in the context of India. **(150 words) 10**
किसी अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास स्वयं ही सार्वभौमिक मूलभूत आय की आवश्यकता को नकारता है। भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

समावेशी विकास से आशय है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना।

सार्वभौमिक मूलभूत आय, प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आय सुनिश्चित करना।

समावेशी विकास के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की आय विकास के माध्यम से ही बढ़ जाएगी। इसके कारण सार्वभौमिक मूलभूत आय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

UBI के पक्ष में तर्क :-

1. आय के असमान वितरण को कम करेगी
2. UBI भारत के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के विकल्प के रूप में हो सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. सब्सिडी को तार्किक कर सकती है।

UBI के विपक्ष में तर्क :-

1. भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के पास संसाधनों का अभाव।
2. UBI के क्रियान्वयन में अनेक चुनौति विद्यमान है।

इसके लिए हमें गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाए रखने चाहिए। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत के सतत एवं दीर्घकालिक विकास हेतु समावेशी आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. E-commerce holds the potential to revamp agriculture marketing in India in multiple ways. Discuss with suitable examples. **(150 words) 10**

ई-कॉमर्स भारत में अनेक तरीकों से कृषि विपणन में सुधार लाने की क्षमता रखता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए।

भारत के कृषि विपणन ~~क्षेत्र~~ से आशय कृषकों के उत्पादों का उचित मूल्य एवं उपभोक्ताओं को उचित खरीद दर सुनिश्चित करने से है।

कृषि विपणन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान

1. कृषि उत्पाद मंडियों के माध्यम से विपणन का होना, प्रतिस्पर्द्धा को खत्म करता है।

2. कीमतों का लाभ कृषकों को नहीं मिलता है। ई-कॉमर्स के माध्यम से उपभोक्ता एवं विक्रेता सीधे व्यापार कर सकते हैं।

3. जल्दी खराब होने वाले उत्पादों हेतु शीघ्र बाजार की उपलब्धता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. FPO के माध्यम से गुणवत्ता एवं उचित कीमत भी सुनिश्चित की जा सकती है।

5. जैविक उत्पादों को उचित बाजार की उपलब्धता।

6. सब्जी एवं फलों के क्रय-विक्रय हेतु बेहतर विकल्प हो सकता है।

अतः ई-कॉमर्स कृषि विपणन की समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह उपभोक्ता एवं कृषकों दोनों के लिए लाभकारी है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While digital financial services can expand financial inclusion in India, there are various challenges that need to be addressed in this regard. Discuss. **(150 words) 10**

जहां डिजिटल वित्तीय सेवाएं भारत में वित्तीय समावेशन का विस्तार कर सकती हैं, वहीं इस संबंध में विभिन्न चुनौतियों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

भारत में 650 मिलयन इंटरनेट उपभोक्ता है। यह वर्ग वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय सेवाओं के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण है।

डिजिटल वित्तीय सेवायें प्रदान करने की चुनौतियाँ:-

1. वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक अंतर (15%)
3. छोटे उपभोक्ता एवं व्यापारियों का कर के दायरे में आने का भय
4. डिजिटल अवसंरचना का अभाव है।
5. डिजिटल नियामक एवं का न होना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. इंटरनेट के प्लेटफोर्मों पर सुरक्षा का अभाव है।

डिजिटल सेवा के गुण :-

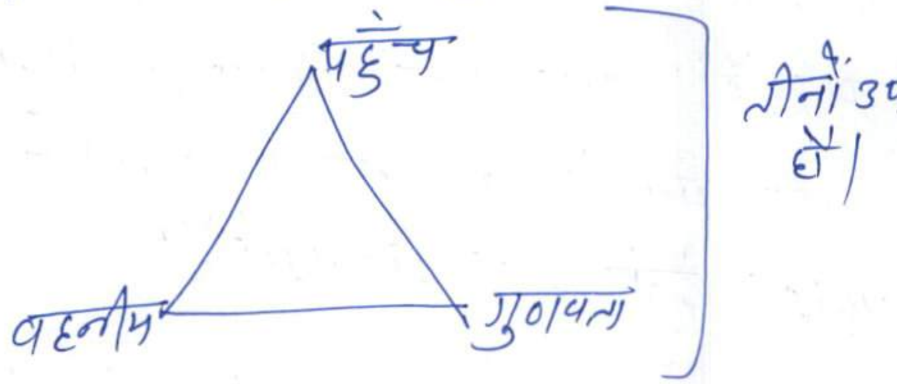

डिजिटल माध्यम से वित्तीय सेवाओं की पहुँच को व्यापक बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार को जागरूकता, साक्षरता एवं अवसंरचना पर ध्यान देना होगा।

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने हेतु डिजिटल वित्तीय समावेशन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. COVID-19 has exposed gaps in India's domestic laws to deal effectively with outbreaks of infectious diseases, especially pandemics. Discuss.

(150 words) 10

कोविड-19 ने संक्रामक रोगों, विशेष रूप से महामारियों के प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने में भारत के घरेलू कानूनों में व्याप्त अंतरालों को उजागर किया है। विवेचना कीजिए।

कोविड -19 ने संपूर्ण विश्व को आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

कोविड -19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी घोषित किया। भारत में प्रथम महामारी है जिसे आपदा के रूप में माना।

कोरोना ने घरेलू कानूनों की कमियों को को उजागर किया :

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम प्राकृतिक आपदा की चुनौती से निपटने हेतु ही बनाया गया था।
2. कोरोना महामारी स्वास्थ्य से संबंधित चुनौती है जबकि निर्देश गृह मंत्रालय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

द्वारा जारी किए गए हैं।

3. लॉकडाउन एवं अन्य पाबंदियों में भी अस्पष्टता थी जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

4. सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी अस्पष्टता।

5. कोरोना महामारी में केन्द्र की भूमिका प्रभावी थी जबकि महामारी के निपटने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

6. प्रवासियों को फेक न्यूज एवं घर पलायन ने एक चुनौति पेश की।

समग्रतः हम कह सकते हैं कि कोरोना के दौरान भारतीय कानूनी ढांचा अपर्याप्त एवं अस्पष्ट था। वस्तुतः यह प्राकृतिक आपदा हेतु ही था।

7. Highlight the need for increasing private sector participation in space sector in India. Enumerate the steps taken by the government recently in this regard. **(150 words) 10**

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इस संबंध में हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध कीजिए।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो की भूमिका महत्वपूर्ण है। वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का योगदान 2% है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आवश्यकता :-

- रणनीतिक लाभ
- संसाधन की अत्याधिक आवश्यकता
- नए उभरते हुए अवसर जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा
- अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसायिक लाभ

भारत सरकार की पहल :-

आत्मनिर्भर भारत में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु निम्न प्रयास किए हैं-

(i) उपग्रह, प्रक्षेपण जैसे नवीन अवसरों तक पहुँच।

(ii) नवीन अवसंरचना के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र हेतु अवसर।

(iii) ग्रह, उपग्रह आदि की खोज में संलग्न करना

2. इनस्पेस :- यह एक स्वायत्त संगठन है जो निजी क्षेत्र को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा

3. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड :- लघु उपग्रह के निर्माण हेतु आरक्षित।

4. मेक इन इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

अतः निजी क्षेत्र हेतु संभावनाओं के दोहन एवं शोध को बढ़ावा देकर वैश्विक अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था में योगदान का बढ़ाना है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. What do you mean by herd immunity? Also discuss the problems with primarily relying on this approach to stop the spread of infectious diseases.
(150 words) 10

हर्ड इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं? साथ ही, संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण पर निर्भर होने से संबंधित समस्याओं की भी विवेचना कीजिए।

हर्ड इम्यूनिटी से आशय टीकाकरण एवं रोग के संक्रमण से प्रतिरोधी रोग के फैलने की दर का नियंत्रण से है।

संक्रामक रोगों के प्रसार हेतु इस दृष्टिकोण की निम्न चुनौति हैं —

1. बडी संख्या में लोगों के संक्रमण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बडे स्तर पर जनहानि के रूप में सामने आ सकती है।

2. कोराना वायरस निरंतर अपने जीन में परिवर्तन कर रहा है।

3. संवेदनशील लोगों पर नकारात्मक प्रभाव जैसे वृद्ध, एवं बच्चे एवं गर्भवती महिला

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. स्पष्टता का अभाव - एक बार संक्रमण से ठीक होने के बाद दुबारा संक्रमित होने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता से कैसे बचेंगे।

अत: हर्ड इम्यूनिटी पर टीके के विकसित होने एवं व्यापक शोध के बाद ही विश्वास कर सकते है।

स्पष्टता के अभाव की स्थिति में बचाव ही उपचार है और दो गज दूरी मास्क है जरूरी के संदेश को अपनाना चाहिए।

9. Despite the acknowledgement of terrorism as a global concern, the Comprehensive Convention on International Terrorism is yet to be adopted. What are the reasons and implications of this impasse?

(150 words) 10

आतंकवाद को एक वैश्विक चिंता के रूप में स्वीकार करने के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अभी तक नहीं अपनाया गया है। इस गतिरोध के कारण और निहितार्थ क्या हैं?

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय 1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तुत प्रस्ताव है। इसमें आतंक की परिभाषा, आतंकवाद के फंडिंग पर नियंत्रण एवं आतंकियों के वैश्विक प्रत्यार्पण जैसे उपाय हैं।

गतिरोध के कारण :-

1. अमेरिका आतंकवाद की परिभाषा एवं राज्य के बल प्रयोग पर असहमत है।
2. मध्यपूर्व के देश की कश्मीर एवं फिलीस्तीन के मुद्दे पर असहमत।
3. अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका की मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

या असहमत है।

आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय न होने के निहितार्थ :-

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु आतंकवाद एक चुनौती है।
2. संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।
3. देशों ने अपने अनुसार घरेलू कानून बनाएं हैं जो नागरिकों के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं।
4. आतंकवाद की व्यापक परिभाषा न होने से कुछ देशों को प्रोत्साहन मिलता है। वे आतंक को विशिष्ट दृष्टिकोण से देखते हैं।

आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय पर व्यापक सहमति बनाकर ही वैश्विक शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. In view of the need for effective border management necessitated by complexity of prevailing challenges, India needs to reform its Border Security Force (BSF). **(150 words) 10**

विद्यमान चुनौतियों की जटिलता द्वारा अनिवार्य बनाए गए प्रभावी सीमा प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए, भारत को अपने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सुधार लाने की आवश्यकता है।

भारतीय सीमा प्रबंधन पड़ोसियों के साथ 15,000 kms स्थलीय एवं 7,500 किमी. समुद्री सीमा साझा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

विद्यमान चुनौती :-

(i) पाकिस्तान के द्वारा आतंक एवं ड्रग्स की अवैध घुसपैठ

(ii) पाकिस्तान की सेना एवं ISIS भी गैर राज्य संगठन की भूमिका में काम करती है।

(iii) उत्तरी सीमाओं पर धरातल का पहाड़ी होना दुर्भेद्य बनाता है।

(iv) बांग्लादेश के साथ नदियों एवं छिद्रित सीमा का होना। यह भी तस्कर एवं अवैध घुसपैठ हेतु सुभेद्य है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सीमा सुरक्षा बल शांति काल में भारत - बंग्लादेश एवं पाकिस्तान सीमाओं पर सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें निम्न सुधार किए जा सकते हैं।

- प्रशिक्षण में आधुनिकीकरण
- कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना।
- बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाना जिससे बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी को प्रभावी नियंत्रण किया जा सके
- कार्मिकों के ड्यूटी के घंटे निर्धारित करना व पर्याप्त अवकाश की अनुमति देना।
- तकनीकी कौशल से युक्त करना

सीमा प्रबंधन सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा, आर्थिक एवं समाजिक विकास को सुनिश्चित करता है। इसके स्मार्ट विजन एवं सर्विलांस महत्वपूर्ण है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Though privatization is considered as a prominent component of economic reforms, India has been ambivalent on the subject even in the post reform period. Discuss. **(250 words) 15**

यद्यपि निजीकरण को आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख घटक माना जाता है, तथापि सुधारोपरांत अवधि में भी भारत इस विषय पर दुविधा की स्थिति में रहा है। विवेचना कीजिए।

1991 में भुगतान संकट के बाद किए गए आर्थिक सुधारों में निजीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है।

निजीकरण के लाभ :-

(i) यह प्रबंधन एवं पूंजी की दक्षता में वृद्धि करती है।

(ii) राष्ट्र के संसाधन एवं करों में भी वृद्धि करता है।

(iii) सरकार अपने महत्वपूर्ण कार्य जैसे शिक्षा स्वास्थ्य एवं जनकल्याण पर ध्यान दे सकती है।

किंतु 1991 के बाद भी भारत में निजीकरण को शंका के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में इसे बाजार के व्यवधान के रूप

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के रूप में माना है।

इसके निम्न कारण हैं :-

1. निजी कंपनियाँ अपने निजी हितों के लिए कार्य करती हैं अनुचित तरीके से संसाधन का आवंटन एवं दुरुपयोग करती है। भारत में 70,000 करोड़ के NPA स्वैच्छिक डिफाल्टर हैं।

2. बैंक ऋण में धोखाधड़ी :- PNB के घोटाले एवं किंगफिशर के संदर्भ में देखा जा सकता है।

3. कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव :- कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव है जैसे सत्यम घोटाला

4. नियामकों का अभाव :- कंपनी अधिनियम

के माध्यम से प्रभावी विनियमन के प्रयास किए गए हैं लेकिन क्रियान्वयन एवं कानूनी बाध्यताएं विद्यमान हैं।

5. लेखों के रखरखाव में मानकता एवं पारदर्शिता का अभाव।

6. निजीकरण एक राजनीतिक दुर्भावना से भी जुड़ा रहता है।

7. व्यवसाय के लाभपूर्ण स्थिति में निजी अभिकर्ता आकर्षित होते हैं।

8. भारतीय जनमानस के पुराने अनुभव निजीकरण को लेकर सही नहीं है।

समग्रतः हम कह सकते हैं कि निजीकरण एक लाभ का सौदा है लेकिन इसमें विनियामक की भूमिका, पारदर्शिता, स्वायत्तता जैसे मुद्दों का समाधान आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Highlighting the potential of micro and small enterprises in the food processing sector, enumerate the challenges that they face. In this regard, discuss the importance of the Scheme for Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (FME). **(250 words) 15**

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए। इस संबंध में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (FME) योजना के महत्व की विवेचना कीजिए।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों का योगदान लगभग 90% है एवं 2/3 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

खाद्य प्रसंस्करण खाद्य सुरक्षा, निर्यात को बढ़ाने एवं किसान की आय दुगुना करने हेतु महत्वपूर्ण है।

चुनौति :-

1. ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना :- ऋण के लिए पर्याप्त कोलैटरल का अभाव होता है जो बैंक से ऋण प्राप्त करने में चुनौति।

2. तकनीकी तक पहुंच का अभाव :- ~~8~~ सूक्ष्म

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एवं लघु उद्यमों के पास तकनीकी क्षमता नहीं होती है।

3. सुरक्षा के मानक :- MSE के स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा मानक की अनुपालना भी नहीं हो पाती है।

4. बाजार की मांग को संबोधित नहीं कर पाती है।

5. उद्योग को स्थापित करने में विभिन्न चुनौतियां का सामना करना पड़ता है।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारीकरण हेतु योजना में सरकार ने वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप उद्योगों को लाभ देने का प्रयास किए हैं।

इसमें MSE की चुनौतियों के समाधान हेतु प्रयास किए है और

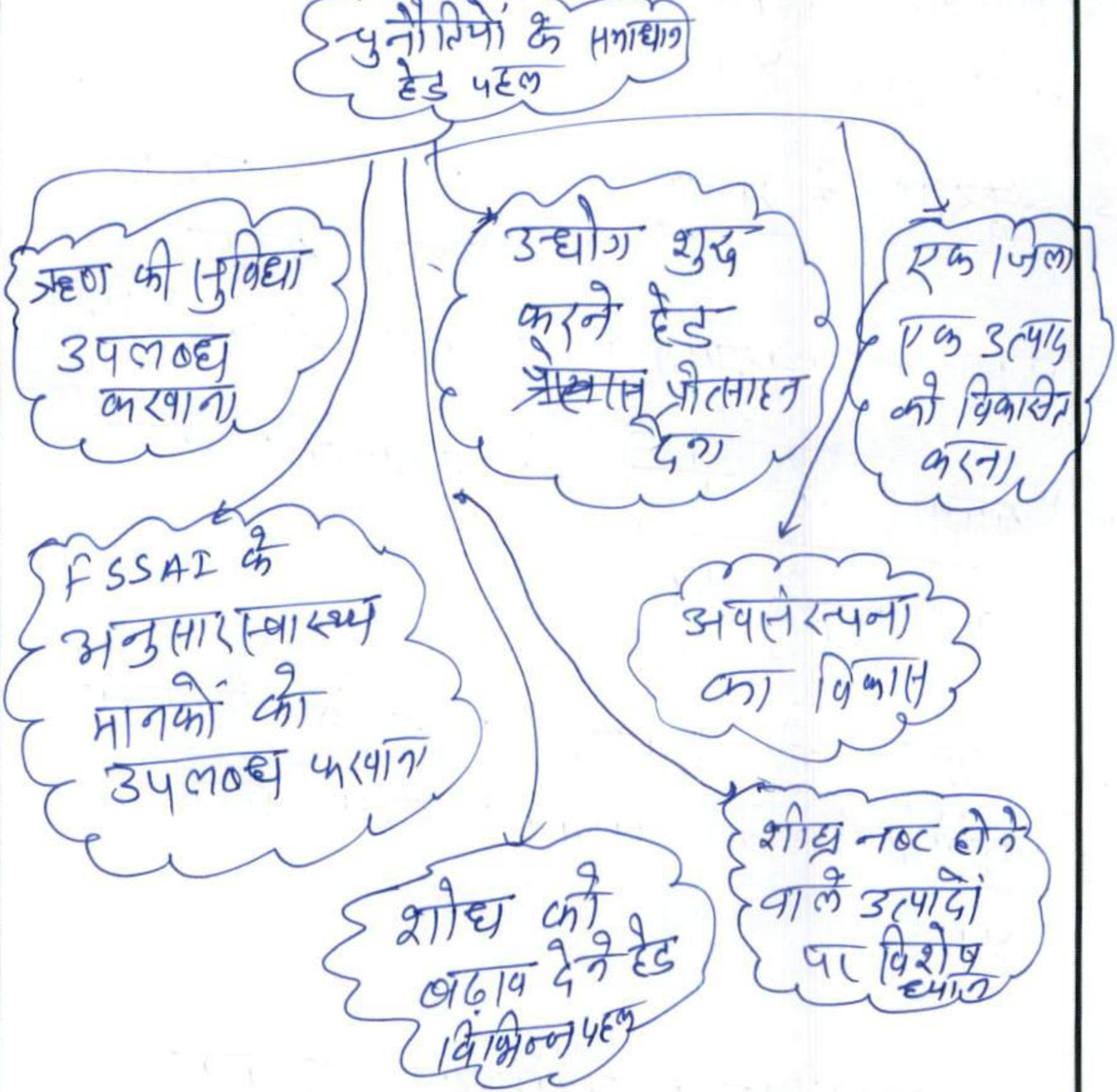

भारत को 5 ट्रिलियन डालर इकोनोमी एवं कोरोना महामारी से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या का समाधान हेतु इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। यह खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Discuss the significance of micro-irrigation in a situation of water crisis in India. Also, mention the challenges with regard to adoption of micro-irrigation systems in India. **(250 words) 15**

भारत में जल संकट की स्थिति को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई के महत्व की विवेचना कीजिए। साथ ही, भारत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने से संबंधित चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत में 4% वैश्विक जल संसाधन उपलब्ध है। कृषि में 85% जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है।

सूक्ष्म सिंचाई का महत्व :-

1. जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग हेतु
2. ऊर्जा की बचत भी करते हैं।
3. कृषि की आगतों का दक्षतम उपयोग जैसे उर्वरक, बीज आदि।
4. नई फसल का समावेशन भी करते हैं।
5. सिंचाई लागत में बचत।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के समक्ष निम्न चुनौतियाँ भी हैं :-

1. विद्युत की आपूर्ति का अनिश्चित होना:- विद्युत की अनिश्चित आपूर्ति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सूक्ष्म सिंचाई को रखने के प्रति प्रवण बनाती है।

2. लागत का अत्यधिक होना :- शुरुआत में सूक्ष्म सिंचाई योजना अत्यधिक महंगी होती है यह भारत के 85% लघु एवं सीमांत किसानों को वंचित करती है।

3. तकनीकी सहायता का भी अभाव है जो रखरखाव एवं परिचालन को प्रभावित करती है।

4. सब्सिडी का समय पर न मिलना एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल न होना।

5. सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के प्रति किसानों में जागरूकता का अभाव।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुधार हेतु प्रयास :

- स्थानीय निकायों की भूमिका को बढ़ावें
- FPO को इस दिशा प्रोत्साहन देना चाहिए
- किसानों को लाभों के प्रति अवगत करवाना
- जल गहन फसलों में अनिवार्य करना

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली किसानों की 2022 तक आय दोगुना करना एवं ~~रोजगार~~ पाँच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. India needs to integrate energy technology innovation in its broader energy policy. Highlighting its significance, mention the steps taken by government in this regard. **(250 words) 15**

भारत को अपनी व्यापक ऊर्जा नीति में ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार को एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

भारत का सतत आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर में वृद्धि ऊर्जा की मांग को भी बढ़ा रहा है। ऊर्जा की यह मांग नवाचार से ही स्वच्छ एवं किफायती कीमतों पर पूरी हो सकती है।

ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार की आवश्यकता

- 2030 तक दोगुनी ऊर्जा मांग की पूर्ति
- INDC लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में
- कोयले पर 65% निर्भरता को कम करना
- पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान जैसे NCR में प्रदूषण
- नवीन प्रौद्योगिकी का लाभ

ऊर्जा प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने निम्न प्रयास किए हैं:-

1. प्रधानमंत्री जैव ईंधन नीति 2018 के माध्यम से पेट्रोल में 30% एवं डीजल में 5% जैव ईंधन का उपयोग करना।
2. भारत में ओजोन की सुरक्षा हेतु शीतलन प्रौद्योगिकी का बढ़ावा
3. मिशन इनोवेशन की शुरुआत।
4. सौर ऊर्जा हेतु सौर अलायंस का गठन
5. वैश्विक स्तरीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा जैसे BS-VI वाहन का उपयोग।
6. ई-मोबिलिटी को बढ़ावा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन
8. नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन

सरकार को स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु शोध को बढ़ावा देना होगा। शोध को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न संगठन, मंत्रालयों एवं निजि क्षेत्र के स्तर पर समन्वय करना होगा।

सरकार के स्तर पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देकर ही स्वच्छ वायु, जल एवं पर्यावरण और लोगों के जीवनस्तर को सुधारा जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Discuss how the idea of Aatmanirbhar Bharat goes beyond the traditional view of self-reliance. **(250 words) 15**

चर्चा कीजिए कि आत्मनिर्भर भारत का विचार किस प्रकार आत्मनिर्भरता के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे है।

आत्मनिर्भर भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सक्रिय भागीदारी से संबंधित है। यह विश्व के व्यापार एवं में वृद्धि हेतु भारत की अवसंरचना के निर्माण से संबंधित है।

आत्मनिर्भरता का पारंपरिक दृष्टिकोण	आत्मनिर्भर भारत
1. आयात प्रतिस्थापन	आयात व्यापार को बढ़ावा देने हेतु
2. केन्द्रीकृत टॉप डाउन मॉडल	विकेन्द्रीकृत मॉडल
3. सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा क्रियान्वयन	निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना
4. विनियमन आधारित	- सरकार सेवा प्रदाता की भूमिका में।

आत्मनिर्भर भारत के तत्व :-

1. ~~आयात को~~ निर्यात को बढ़ावा देना :- इसमें निर्यात मार्केट का विविधीकरण करना। व्यापार घाटे को कम करने पर ध्यान दिया गया है।

2. निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका :- निजी क्षेत्र को व्यापार, सब्सिडी की सुविधा प्रदान की गई हैं जिससे उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

3. सुरक्षा जाल प्रदान करना :- श्रमिकों, उद्योगों को सुरक्षा जाल प्रदान करना।

4. भारतीय उद्यमिता को बढ़ावा :- भारत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु।

5. लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना। इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ेगी।

6. बदलती हुई वैश्विक राजनीति संरचना एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में सक्रिय भूमिका।

आत्मनिर्भर भारत की पहल प्रगतिशील है। इसको सफल बनाने हेतु कौशल एवं रोजगार पर बल, अवसंरचना एवं सब्सिडी की दिशा में सुधार करना होगा।

भारत को पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था एवं किसान की आय दोगुनी करने की के लक्ष्यों की की प्राप्ति आत्मनिर्भर भारत के सफल क्रियान्वयन में है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. The increased frequency and intensity of climate extremes in the Indian subcontinent can have grave implications. Comment. Also, suggest some measures that can be taken towards building climate-resilience in India. **(250 words) 15**

भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु की चरम स्थितियों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, भारत में जलवायु-प्रत्यास्थता निर्माण की दिशा में उठाए जा सकने वाले कुछ कदमों का भी सुझाव दीजिए।

भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले वर्षों में अनेक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन समुद्र पारिस्थितिकी हिमालय एवं कृषि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है।

जलवायु की चरम स्थिति ~~क्षे~~

1. महासागर जल स्तर का ~7 CM बढ़ना।
2. ~~+~~पिछले पाँच दशकों में ~~समुद्र~~ हिमालय के ग्लेशियर में परिवर्तन।
3. मानसून के विचलन में 6% तक की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
4. चक्रवातों की आवृत्ति एवं तीव्रता

में वृद्धि।

5. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि।

जलवायु प्रभावस्थता के गंभीर निहितार्थ ~~की दिशा में पहल~~ :-

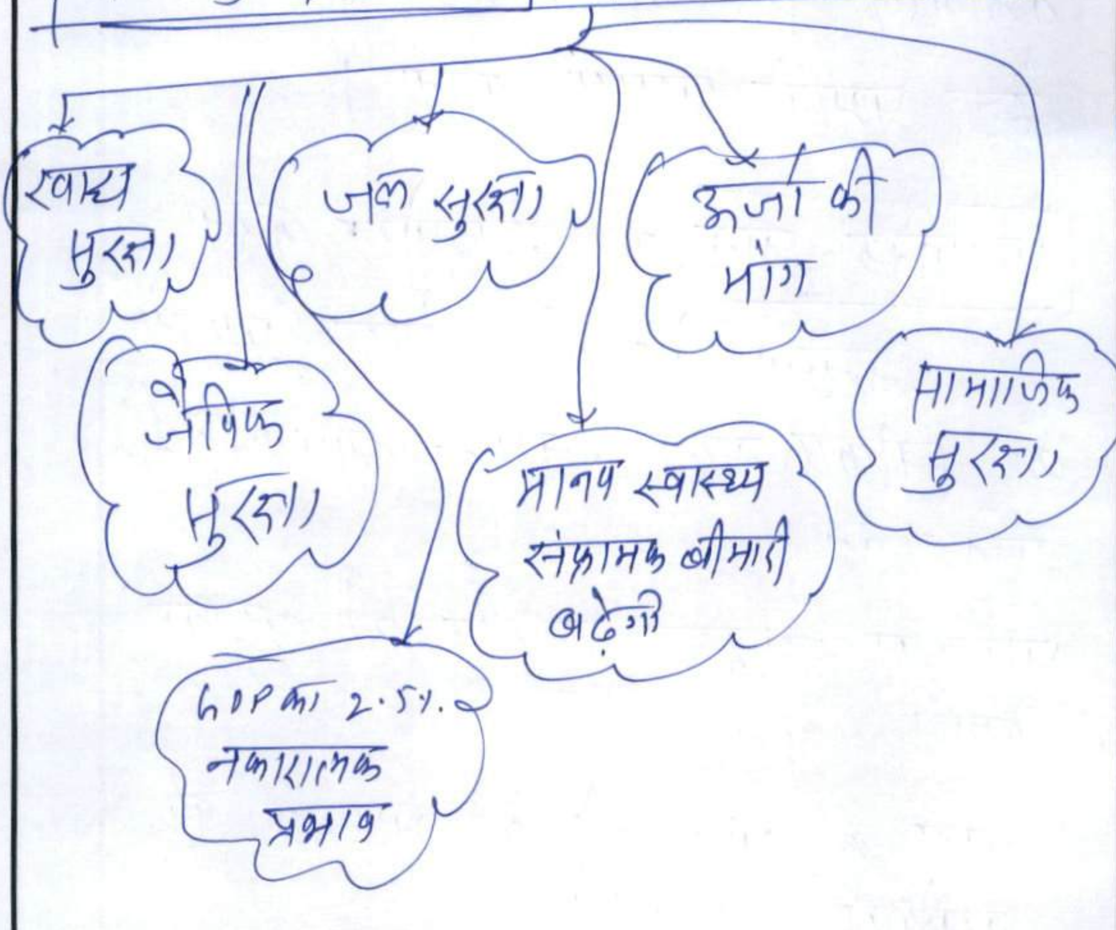

जलवायु परिवर्तन की दिशा में पहल

1. दीर्घकालीन योजना का निर्माण एवं सुभेद्यता का आंकलन करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. क्षेत्रीय स्तर पर शोध को बढ़ावा देकर वास्तविक प्रभावों का आंकलन करना।

3. वनीकरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास करना।

4. पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना :- जनजातियों की श्रेष्ठ प्रथाओं को स्वीकार करना जैसे- बांस सिंचाई, पवित्र वन।

5. पर्यावरण अनुकूल तकनीक को बढ़ावा देना।

6. जनता की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण।

~~अतः~~ पर्यावरण के साथ ही मानव अस्तित्व है और सतत एवं समावेशी विकास में ही मानव का कल्याण निहित है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Approach to flood control in India should evolve from piecemeal measures to an integrated basin management. Comment. **(250 words) 15**

भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए खंडित रूप में उपाय करने वाला दृष्टिकोण क्रमिक रूप से एकीकृत बेसिन प्रबंधन के रूप में विकसित होना चाहिए। टिप्पणी कीजिए।

भारत में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की घटनाएं देखी जाती हैं। बाढ़ प्रबंधन आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है।

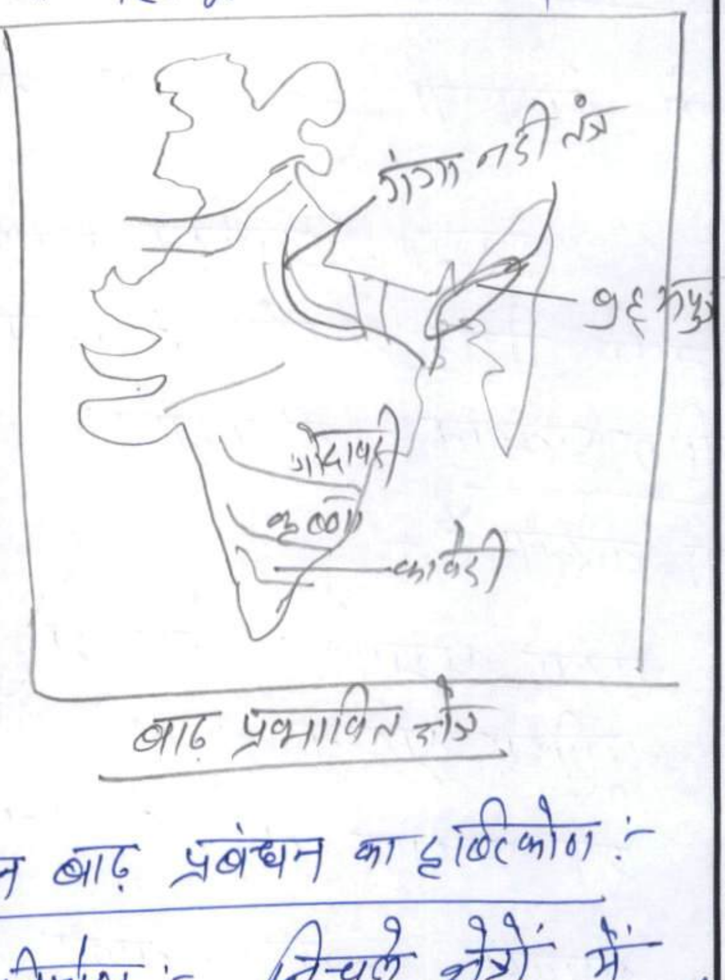

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

भारत में वर्तमान बाढ़ प्रबंधन का दृष्टिकोण :-

1. बांधों का निर्माण :- निचले क्षेत्रों में जल प्लावन की समस्या के लिए उत्तरदायी होता है।

2. तटबंधों का निर्माण :- यह नदी में ऊपरी

भागों के जल को प्रवेश से रोकता है। ~~अल~~ नदी के उफान के बाद भी चुनौति पैदा करता है।

3. गाद का तल से निकालना :- नदी से गाद को निकालना चुनौतिपूर्ण बनी हुई है।

समग्रत: उपर्युक्त प्रचलित प्रणालियाँ चुनौति पैदा करती हैं जबकि एकीकृत बेसिन प्रबंधन दीर्घकालिक समाधान पेश करता है -

1. सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करना। जैसे कृष्णा एवं पेन्नार नदी के जल का सदुपयोग

2. भाखड़ा - नांगल बांध के माध्यम अतिकृत जल के बहु आयामी उपयोग। विद्युत, सिंचाई पर्यटन आदि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. यह एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें नदी बेसिन में वृक्षारोपण जैसे बाढ़ नियंत्रण उपायों को भी सम्मिलित करते हैं।

4. सभी हितधारकों की पर्याप्त भागीदारी।

5. संपूर्ण बेसिन का समग्रता के साथ प्रबंधन।

समग्रतः हम कह सकते हैं कि एकीकृत बाढ़ प्रबंधन की रणनीति को अपनाकर ही कृषि में सिंचाई, जल का इष्टतम उपयोग एवं बेसिन का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. What do you understand by Convalescent Plasma Therapy? Enumerate the potential uses and concerns in its application. **(250 words) 15**

कॉन्वलेसंट प्लाज्मा थेरेपी से आप क्या समझते हैं? इसके संभावित उपयोगों और अनुप्रयोग में सम्मिलित चिंताओं का उल्लेख कीजिए।

कॉन्वलेसंट प्लाज्मा थेरेपी
किसी रोग की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के बाद प्लाज्मा को निकालकर रोगी के उपचार हेतु उपयोग में लेना।

यह थेरेपी कोरोना महामारी में उपयोगी साबित हुई है।

प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग :-

1. H_1N_1 वायरस के संक्रमण से लड़ने हेतु भी बेहतर उपयोग
2. सार्स-2 (2003) में भी इलाज हेतु उपयोग।
3. 1918 में स्पेनिश फ्लू के लिए भी लाभकारी साबित हुई।
4. इसका प्रयोग चिकित्सा कर्मियों हेतु

भी रोग प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करने में किया जा सकता है।

संबंधित चिंताएँ :-

1. रक्त तत्वों का स्थानान्तरण :- इसमें रक्त में अज्ञात हानिकारक तत्वों का भी स्थानान्तरण होगा।

2. परवर्ती हानिकारक लक्षण :- प्लाज्मा थैरेपी के बाद का पर्याप्त शोध करना चाहिए जिससे इसके परिणामों को देख सकते हैं।

3. पर्याप्त रूप से दाता का नहीं मिल पाना।

4. सीमित संख्या में टेस्टिंग :- कोरोना के परिणामों को देखने हेतु टेस्टिंग को बढ़ाना होगा और उनके निष्कर्षों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

का विश्लेषण करना होगा।

5. उच्च जोखिमों से युक्त रोगी

6. प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए।

समग्रतः हम इसको उपयोग में लाने हेतु व्यापक स्तर पर डेटा का विश्लेषण करना होगा। गंभीर रोगियों के जीवन को बचाने हेतु उपयोग में लेना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Given the diverse security challenges as well as external and internal linkages, developing a National Security Strategy for India requires a comprehensive approach. Explain. **(250 words) 15**

विविध सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ बाह्य और आंतरिक जुड़ाव को देखते हुए, भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। स्पष्ट कीजिए।

भारत वर्तमान समय में आंतरिक और बाह्य स्तर पर सोश्लिष्ट और व्यापक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है।

बाह्य चुनौति :

1. पाकिस्तान के साथ पारंपरिक ~~सीमा~~ विवाद एवं आतंक को भारत में बढ़ावा देना।
2. चीन के साथ सीमा विवाद
3. रोहिंग्या संकट

आंतरिक चुनौति

1. नक्सलवाद
2. उग्रवाद - पूर्वोत्तर भारत
3. नशे की बढ़ती चुनौति

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. विविधता (धर्म, जाति) का प्रबंधन

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना:-

1. आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों की स्पष्ट पहचान :- घरेलू चुनौतियाँ भी बाह्य कारकों से प्रभावित होती है जैसे नशे की प्रवृत्ति एवं आतंक का पड़ोसी देशों का प्रभाव।

2. बाह्य चुनौतियों हेतु कूटनीतिक एवं सैन्य प्रबंधन पर बल देना।

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना एवं विकास को बढ़ावा देना।

4. आंतरिक चुनौतियों के मूलभूत कारण अशिक्षा, गरीबी एवं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बेरोजगारी का समाधान करना।

5. साइबर सुरक्षा पर विशेष बल देना।

6. अंतरिक्ष में भी अपने उपग्रहों की सुरक्षा पर बल।

7. सैन्य बलों का आधुनिकीकरण

8. पुलिस बल आधुनिक एवं प्रशिक्षण क्षमताओं से युक्त हो।

9. आंतरिक सुरक्षा हेतु जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो।

समग्रतः भारत की आंतरिक एवं बाह्य चुनौती संश्लिष्ट हैं। इन्हें समग्र, बहुआयामी एवं व्यापक दृष्टिकोण से ही समाधान कर सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. What do you understand by Critical Information Infrastructure? Highlight the significance of Critical Information Protection and state the measures taken to ensure the same. (250 words) 15

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण सूचना संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना ऐसे सूचना प्रौद्योगिकरण के उपकरणों से संबंधित है जिनके प्रभावित होने से आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो।

महत्वपूर्ण सूचना संरक्षण का महत्व :

1. 2014 के बाद साइबर हमलों में 23% तक वृद्धि हुई है।
2. 650 मिलयन लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
3. डिजिटल सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है।
4. निजता एवं महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. परस्पर निर्भरता में भी वृद्धि हुई है।

6. परमाणु संयत्रों की सुरक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता विभिन्न खतरों को भी बढ़ाती है। इस क्षेत्र में सरकार ने निम्न उपाय किए हैं।

1. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केन्द्र की स्थापना।
2. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
3. कम्प्यूटर इमरजेन्सी रेस्पोन्स टीम का गठन।
4. C-DEC का गठन
5. नेशनल साइबर को ऑर्डिनेशन का गठन।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. तीनों सेनाओं की एक इकाई के माध्यम डिफेंस सुरक्षा सुनिश्चित

7. साइबर एवं डिजिटल को Key security importance के रूप में पहचान की है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करके ही 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा एवं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।